RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 3 JULY TO 9 JULY 2024 प्रति बुधवार वर्ष 09 अंक 41 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट सोना 122 रुपये टूटा, चांदी 81 रुपये फिसली

Page 3

EPFO के लाखों सदस्यों की बल्ले-बल्ले...

Page 4

स्टार हैल्थ इंश्योरेंस ने 50 शहरों और कस्बों में अपनी होम हैल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराईं

Page 5

editorial

जीएसटी के सात साल

स्वतंत्र भारत के इतिहास में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था कराधान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है. इसका प्रारंभ एक जुलाई, 2017 को हुआ था. बीते सात वर्षों में कर स्तर में निरंतर बेहतरी आयी है, जिससे उपभोक्ताओं को उल्लेखनीय लाभ हुआ है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन में इंगित किया गया है कि इस प्रणाली के आने से पारिवारिक खर्च में कम से कम चार प्रतिशत की बचत हुई है. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में घरेलू आवश्यकताओं, विशेष रूप से खाने-पीने की वस्तुओं की मुद्रास्फीति चिंताजनक रही है. ऐसे में यदि जीएसटी व्यवस्था नहीं होती, तो परिवारों पर बहुत दबाव बढ़ जाता. पहले जो व्यवस्था थी, उसमें जटिलता थी, पारदर्शिता का अभाव था और राजस्व संग्रहण भी अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाता था. केंद्र और राज्य अलग-अलग कर लगाते थे और करों के कई प्रकार भी थे. अब केंद्र और राज्य के जीएसटी होते हैं, जो जुड़ी हुई प्रणाली से संचालित होते हैं. समूचे देश में एक कराधान होने से इन समस्याओं का समाधान हुआ है. बीते वर्षों में जीएसटी चुकाने और रिटर्न की वापसी को तकनीक की मदद से अधिक पारदर्शी भी बनाया गया है तथा पूरी प्रक्रिया भी सरल हुई है. हालांकि कर चोरी की समस्या अभी भी बनी हुई है, जिसके लिए आधार संख्या आधारित रिटर्न भरने का प्रावधान किया जा रहा है, पर इसमें बहुत कमी आयी है. यह राजस्व बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है. बीते माह 1.74 लाख करोड़ रुपये जीएसटी का संग्रहण हुआ है. यह आंकड़ा मई में 1.73 लाख करोड़ रुपया रहा था. अप्रैल में तो यह दो लाख करोड़ रुपये से अधिक था. बाद के दो माह में कमी की मुख्य वजह अत्यधिक तापमान रहा, जिससे औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ा. वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 5.57 लाख करोड़ रुपये संग्रहित हुए हैं. अब इसमें लगातार वृद्धि का अनुमान है क्योंकि मानसून के सामान्य रहने की आशा है तथा अर्थव्यवस्था का भी विस्तार हो रहा है. इस कर व्यवस्था के तहत दरों का निर्धारण जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाता है. इस काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री का उत्तरदायित्व है. सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त अधिकारी इसके सदस्य होते हैं. आम तौर पर निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं. जीएसटी दरों को लेकर टकराव के उदाहरण न के बराबर हैं. जीएसटी ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया है, तो उत्पादकों और विक्रेताओं को भी सहूलियत हुई है. आशा है कि अनुभव बढ़ने के साथ-साथ इस व्यवस्था में उत्तरोत्तर बेहतरी आयेगी.

अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधार के रूप में जीएसटी का कैसा रहा सफर, क्या खोया-क्या पाया

नई दिल्ली। एजेंसी

वस्तु और सेवा कर या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को देशभर में लागू हुए 7 साल हो गए हैं. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था. इस जीएसटी के अंदर 17 लोकल टैक्स और चार्ज समाहित किए गए थे।

वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर लिखा है कि...जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम सुधार से लचीलेपन में बदल दिया है और टैक्सपेयर्स, अन्य हितधारकों और आम जनता को फायदा पहुंचाया है। बीती जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोहराया कि मैं टैक्सपेयर्स को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हमारा इरादा जीएसटी टैक्सपेयर्स की जिंदगी को आसान बनाना है। इससे पहले भी इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए लिख चुकी हैं- 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आटा, सौंदर्य प्रसाधन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि सहित अधिकांश घरेलू सामान जीएसटी के दायरे में आने के बाद सस्ते हो गए हैं।'

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन सात सालों में आम लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स में आई कमी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था. इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को जीएसटी से हुए फायदों के बारे में जानकारी दी थी।

पीएम मोदी ने लिखा कि जीएसटी के जरिए सुधार हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है। इससे गरीबों और आम आदमी को काफी बचत हुई है. हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पीएम मोदी ने इसके साथ जो डाटा लगाया, उसके मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (सीबीआईसी) के आंकड़ों की मानें तो जीएसटी लागू होने के बाद आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर सहित ज्यादातर घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं. वहीं, इस तरह से घरेलू सामान के सस्ता होने से लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो गया है और लोगों की बचत करने की क्षमता में भी सुधार हुआ है।

जीएसटी के जरिए कैसे हुआ टैक्स सिस्टम आसान

जीएसटी देश में एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था. इसने 17 लोकल टैक्स और 13 सरचार्ज को फाइव लेयर सिस्टम में व्यवस्थित किया, जिससे टैक्स सिस्टम आसान हो गया. इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबार की सीमा गुड्स के लिए 40 लाख रुपये और सर्विसेज के लिए 20 लाख रुपये हो गई. वैट के तहत यह सीमा औसतन पांच लाख रुपये से ऊपर थी।

जीएसटी से मिले कई फायदे

सात साल पहले पेश किए गए जीएसट ने टैक्स कंप्लाइंस को आसान बनाया है और इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा जिससे राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी हुई।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी ने टैक्स उछाल को बढ़ाकर साल 2018-23 के दौरान 1.22 पर कर दिया है जो जीएसटी से पहले 0.72 पर था।मुआवजा खत्म होने के बावजूद राज्यों का टैक्स उछाल 1.15 पर बना हुआ है।

जीएसटी के बाद राज्यों का वास्तविक राजस्व 46.56 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है वरना जीएसटी के बिना वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक राज्यों का राजस्व 37.5 लाख करोड़ रुपये होता। साल 2017 से लागू होने के बाद औसत जीएसटी दर में लगातार गिरावट आई है और जीएसटी ने कई जरूरी चीजों पर टैक्स को जीएसटी से पहले की तुलना में कम कर दिया है। हेयर ऑयल और साबुन जैसी आम वस्तुओं पर कर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज पर टैक्स 31.5 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया. जीएसटी ने कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छूट दी है, जैसे बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ, कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटरी नैपकिन, हियरिंग एड्स के पार्ट्स, एग्रीकल्चर सर्विसेज आदि। जीएसटी अपैलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना होने से इंडस्ट्री के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है।

जीएसटी की उलब्धियां

जीएसटी ने राज्यों में 495 अलग-अलग औपचारिकताओं जैसे चालान, फॉर्म, घोषणाएं वगैरह को भी घटाकर सिर्फ 12 कर दिया है. पिछले सात सालों में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या 65 लाख से बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई है. जीएसटी से एवरेज मंथली रेवेन्यू बढ़कर 2024-25 में लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ये काफी अच्छी ग्रोथ कही जा सकती है क्योंकि साल 2017-18 में लगभग 90,000 करोड़ रुपये रही थी।

जीएसटी की राह में अभी भी चुनौतियां

वित्तीय जानकारों का मानना है कि दूसरी ओर टैक्स चोरी करने वाले सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए नए-नए तरीके खोज रहे हैं। टैक्स अधिकारी फर्जी चालान बनाने और फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की घटनाओं से जूझ रहे हैं। फर्जी चालान और धोखे से रजिस्ट्रेशन की घटनाएं अभी भी टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। वर्ष 2023 में जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) ने 1.98 लाख करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का पता लगाया। इसके अलावा सरकारी खजाने को चूना लगाने में शामिल 140 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया. इसके जरिए ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, इंश्योरेंस और सेकंडमेंट जैसे अलग-अलग सेक्टर में महत्वपूर्ण जीएसटी चोरी का पता चला।

बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट

सोना 122 रुपये टूटा, चांदी 81 रुपये फिसली

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती पर अनिश्चितता के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मंदी के रुख को देखते हुए मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर वायदा कारोबार में अगस्त डिलीवरी वाला

सोना 122 रुपये या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71,532 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान दौरान कीमती धातु 71,432 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई। हाजिर और वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। एमसीएक्स पर सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 81 रुपये की गिरावट के साथ 89,669 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। मंगलवार को मुंबई के हाजिर बाजार में सोना 71,692 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी में 88,015 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार होता दिखा। बाजार सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के स्थानीय बाजारों में कीमती धातु 74,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर लगभग स्थिर रही। चांदी में कारोबार 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर होता दिखा। सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में दिखी। इससे बाजार सहभागियों को बढ़त मिली।

तीन अरब डॉलर जुटाने के लिए देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी हुंडई

नई दिल्ली। एजेंसी

दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता हुंडई मोटर की भारतीय इकाई ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा कराए हैं। कंपनी ने आईपीओ के तहत 14.22 करोड़ शेयर बेचने की पेशकश की है। शेयर बिक्री के लिए सलाहकारों में सिटीग्रुप इंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी और मॉर्गन स्टेनली को शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 24 में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पैसेंजर सेल्स वॉल्यूम के मामले में मारुति सुजुकी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता है। इभ23 में हुंडई का राजस्व ?60,000 करोड़ रुपये रहा जबकि इसका मुनाफा ?4,653 करोड़ रुपये रहा। यह

एलआईसी को पीछे छोड़ने की तैयारी

देश में गैर-सूचीबद्ध कार निर्माताओं में सबसे अधिक है

आईपीओ के माध्यम से हुंडई लगभग 3 बिलियन डॉलर जुटाने की कोशिश करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आईपीओ के बाद साल के अंत तक संभावित रूप से शेयरों की लिस्टिंग की योजना बनाई गई है। अगर योजना के अनुसार कंपनी का आईपीओ धरातल पर उतरता है तो यह 2022 में आए भारतीय जीवन बीता निगम के ₹2.5 बिलियन इश्यू को पार करते हुए भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा।

कंपनी ने कहा है कि उसने 10 रुपये अंकित मूल्य के 142,194,700 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लाभों को प्राप्त करना है। कंपनी को उम्मीद है कि इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग उसकी दृश्यता और ब्रांड छवि को बढ़ाएगी और भारत में इक्विटी शेयरों के लिए तरलता और सार्वजनिक बाजार प्रदान करेगी।

देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई के आईपीओ प्रस्ताव (ॲप्झ) के अनुसार कंपनी के बिक्री के जारी किए गए शेयरों में 50 प्रतिशत शेयर क्यूआईबी यानी संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित होंगे। 35इ शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं, 15 प्रतिशत शेयर गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित होंगे।

हुंडई की ओर से दिए गए विवरण के अनुसार अपनी स्थापना के बाद दिसंबर 2023 तक कंपनी ने अपने भारतीय परिचालन में ₹5.04 बिलियन (रु. 29740 करोड़ लगभग) का निवेश किया है। हुंडई मोटर्स के वित्तीय वर्ष 2023 के आंकड़े बताते हैं कि कैसे दो दशकों में कंपनी को एक लाभ कमाने वाली फर्म में बदला गया। भारतीय शेयर बाजारों में उम्मीद को देखते हुए कंपनी का मानना है कि प्रवर्तकों के लिए अपनी हिस्सेदारी आंशिक रूप से कम करने का यह सही मौका है। कंपनी का भारतीय परिचालन दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तेज गति से बढ़ रहा है। कंपनी का मानना है कि शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग से इसके मूल्य व पहचान में सुधार होगा।

शीर्ष 18 राज्यों का राजस्व चालू वित्तीय वर्ष में बढ़कर 38 लाख करोड़ पर पहुंच सकता है, क्रिसिल का दावा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के शीर्ष 18 राज्यों राजस्व चालू वित्तीय वर्ष में आठ से 10 प्रतिशत तक बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है। इन राज्यों की देश की जीडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में 90 की हिस्सेदारी है। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इन 18 राज्यों का राजस्व सात प्रतिशत की दर से बढ़ा था। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों के राजस्व में इजाफे का सबसे मुख्य कारण मजबूत जीएसटी संग्रह और केंद्र से राज्यों को इसका हस्तांतरण होगा। राज्यों के राजस्व में इस मद से आमदनी की हिस्सेदारी करीब 50% है। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों को शराब की बिक्री से होने वाली आमदनी जो इनके राजस्व का 10 प्रतिशत है, स्थिर रहने अनुमान है। वहीं, पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए बिक्री कर का संग्रह और 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान मामूली रह सकता है।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि राजस्व वृद्धि को सबसे अधिक गति कुल राज्य जीएसटी संग्रह, बेहतर कर अनुपालन और अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिकरण से मिलती रहेगी। चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय कर हस्तांतरण में 12 से 13 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है जो अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चालक साबित होगा। केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान में चार से पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो बजट परिव्यय के अनुरूप है। क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा है कि गणना में इस वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्व में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों को अपने राजस्व का विस्तार करने और संग्रह क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई महीने में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। इस बजट में राज्यों का राजस्व बढ़ाने की दिशा में केंद्र की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर स्थिति और साफ होगी।

एसएंडपीः राजकोषीय घाटा कम हुआ तो 24 माह में बढ़ सकती है भारत की रेटिंग, 6.8 फीसदी रह जाएगी जीडीपी की वृद्धि दर

नई दिल्ली। एजेंसी

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है कि केंद्र सरकार अगर देश के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के चार फीसदी तक लाने में सक्षम रहती है तो अगले 24 महीनों में भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ सकती है। रेटिंग एजेंसी के निदेशक (सॉवरेन रेटिंग्स) यीफार्न फुआ ने बुधवार को कहा, केंद्र और राज्यों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के सात फीसदी से कम होना चाहिए। इसमें ज्यादा योगदान केंद्र का होना चाहिए। रेटिंग एजेंसी ने इसी साल मई में रेटिंग को 'बीबीबी-' पर बरकरार रखते हुए भारत के लिए आउटलुक को स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया था।

6.8 फीसदी रह सकती है जीडीपी की वृद्धि दर

केंद्र सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.63 फीसदी से कम होकर 5.1 फीसदी पर आ जाएगा। सरकारी खर्च व राजस्व के बीच का अंतर 2025-26 तक और घटकर 4.5 फीसदी के स्तर पर आ सकता है। एसएंडपी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.8 फीसदी रहेगी, जो पिछले वित्त वर्ष के 8.2 फीसदी से कम है।

सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर, तेल कंपनियों ने 30 रुपये घटाए दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। तेल विपणन कंपनियों की ओर से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया गया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में आज यानी 1 जुलाई से 30 रुपये की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत आज से 1646 रुपये हो गई है। हाल के महीनों में लगातार वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। 1 जून को 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 69.50 रुपये की कटौती की गई थी, जिससे कीमत घटकर 1,676 रुपये हो गई थी। इससे पहले 1 मई, 2024 को प्रति सिलेंडर 19 रुपये की एक और कटौती हुई थी। कीमतों में लगातार कटौती से चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में परिचालन लागत से जूझ रहे कारोबारों को राहत मिली है।

जेफरीज की रिपोर्ट में दावा

भारत सबसे बड़ा विवाह स्थल, हर साल होती हैं एक करोड़ तक शादियां

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत दुनिया का सबसे बड़ा विवाह स्थल है। यहां हर साल 80 लाख से एक करोड़ शादियां होती हैं, जबकि चीन में 70-80 लाख और अमेरिका में 20-25 लाख विवाह होते हैं। खास बात है कि आम देशवासी शिक्षा (स्नातक तक) की तुलना में विवाह समारोह पर दोगुना खर्च करते हैं। अमेरिकी जैसे देशों में यह खर्च शिक्षा की तुलना में आधे से भी कम है।

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय विवाह उद्योग का आकार करीब 10 लाख करोड़ रुपये का है। यह अमेरिका के विवाह उद्योग का लगभग दोगुना है। हालांकि, चीन की तुलना में छोटा है। अमेरिका में विवाह उद्योग का आकार 5.84 लाख करोड़ रुपये (70 अरब डॉलर) का है, जबकि चीन में यह 14.2 लाख करोड़ (170 अरब डॉलर) का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय शादी कई दिनों तक चलती हैं और साधारण से लेकर बेहद भव्य तक होती हैं। इसमें क्षेत्र, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लाख करोड़ है भारतीय विवाह उद्योग का आकार, अमेरिका की तुलना में करीब दोगुना

भारत में एक शादी पर औसतन 12.50 लाख रुपये (15,000 डॉलर) खर्च होते हैं। यह रकम प्रति व्यक्ति या घरेलू आय का कई गुना है।

शादियों में होने वाले कुल खर्च में दुल्हन के आभूषणों की हिस्सेदारी आधे से अधिक होती है।

लग्जरी सेगमेंट में दुल्हन के लहंगों में भारी जटिल काम शामिल होता है। कुछ मामलों में इन लहंगों का वजह 10 किलोग्राम तक भी हो सकता है।

खर्चीली शादियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद विदेशी स्थानों पर होने वाली आलीशान शादियां भारतीय वैभव को प्रदर्शित करती रहती हैं।

आभूषण, गाड़ियों समेत अन्य उत्पादों की बढ़ जाती है खपत

जेफरीज ने कहा, भारत में शादियां भव्य होती हैं। इनमें कई तरह के समारोह और खर्च होते हैं। शादियों के सीजन में आभूषण समेत कई उद्योगों में बिक्री बढ़ जाती है। शादियों के सीजन में आभूषण और परिधान जैसी श्रेणियों में खपत बढ़ती है। अप्रत्यक्ष रूप से ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लाभ मिलता है।

खाद्य-किराना के बाद दूसरा बड़ा उद्योग

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में खपत श्रेणी में शादियों का दूसरा स्थान है। अगर शादी एक श्रेणी होती, तो खाद्य और किराना के बाद दूसरी सबसे बड़ी खुदरा श्रेणी होती। भारतीय खाद्य और किराना उद्योग का आकार 56.8 लाख करोड़ रुपये (681 अरब डॉलर) है।

EPFO के लाखों सदस्यों की बल्ले-बल्ले...

पेंशन को लेकर सरकार ने बदला ये बड़ा नियम!

नई दिल्ली। एजेंसी

EPS के तहत जो लोग 10 साल से पहले योजना को छोड़ देते थे, उन्हें विड्रॉल की सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से पहले इस योजना को छोड़ने वाले लोगों को अपने कंट्रीब्यूशन पर विड्रॉल की सुविधा नहीं दी जाती थी। हालांकि अब ये नियम बदल चुका है।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में बदलाव किया है। अब 6 महीने से कम कंट्रीब्यूट करने वाले सदस्य भी पैसे निकाल सकेंगे। इस बदलाव से ईपीएस के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। दरअसल, हर साल लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 साल वाले अंशदायी सेवा से पहले ही योजना छोड़ देते हैं. इसमें 6 महीने के अंदर ही इस योजना को छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है।

EPS के तहत जो लोग 10 साल से पहले योजना को छोड़ देते थे, उन्हें विड्रॉल की सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से पहले इस योजना को छोड़ने वाले लोगों को अपने कंट्रीब्यूशन पर विड्रॉल की सुविधा नहीं दी जाती थी। हालांकि अब इस नियम को बदलते हुए सरकार ने बड़ी राहत दी है। नए संशोधन से हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलेगा, जो 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं।

सरकार ने इस नियम में भी किया बदलाव योजना को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ईपीएस विवरण में भी संशोधन किया है। अब से विड्रॉल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है। इस नियम से विड्रॉल करने में आसानी होगी। इस बदलाव से 23 लाख से ज्यादा ईपीएस सदस्यों लाभ होगा।

पहले क्या था नियम?

अब तक विड्रॉल बेनिफिट का कैलकुलेशन पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जाती थी, जिस पर ईपीएस अंशदान का भुगतान किया गया है। अंशदायी सेवा के 6 महीने या उससे अधिक समय पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के हकदार होते थे। नतीजतन, 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था।

7 लाख क्लेम हुए खारिज

पुराने नियम के कारण कई दावे खारिज कर दिए गए क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बिना ही बाहर हो रहे थे। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदायी सेवा 6 महीने से कम होने के कारण विड्रॉल बेनिफिट के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए। अब इन ईपीएस सदस्यों को जो 14.06.2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के हकदार होंगे।

ईपीएस क्या होता है?

अक्सर लोग ईपीएस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल यह एक पेंशन स्कीम है, जो ईपीएफओ की ओर से मैनेज किया जाता है। इस स्कीम के तहत 10 साल तक कंट्रीब्यूशन देना होता है, फिर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हकदार हो जाते हैं। इस स्कीम के तहत मौजूदा और नए ईपीएफ मेम्बर शामिल होते हैं। नियोक्ता / कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। हालांकि, कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा EPF में और नियोक्ता / कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में और 3.67% हर महीने EPF में जाता है। कम से कम 10 साल की नौकरी पूरा करने के बाद और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

नेस्ले ने 'उठा मंच, दिखा क्रंच' कैम्पेन शुरू किया

लोगों को मंच के साथ अपना सफर शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एक ऐसी दुनिया में जहाँ आलोचना और संदेह कभी-कभी रचनात्मकता और महत्वाकांक्षाओं को दबा देते हैं, नेस्ले मंच (MUNCH) ने अपना 'उठा मंच, दिखा क्रंच' कैम्पेन शुरू किया है। यह लोगों को अपनी अनोखी विशेषताओं को अपनाने और अपने जुनून को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मंच का हर एक बाइट 'क्रंच' का उत्सव मनाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की अंदरूनी ताकत और दृढ़ता का प्रतीक है। यह उन्हें खुद के प्रति सच्चा रहने और अपने सपनों के पीछे भागने से मिलने वाले आनंदमय पुरस्कारों की याद दिलाता है।

इस कैम्पेन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये, रूपाली रत्तन, डायरेक्टर, कंफेक्शनरी बिजनेस, नेस्ले इंडिया ने कहा, "इस कैम्पेन के माध्यम से, हम चाहते हैं कि मंच (MUNCH) संदेह करने वाले सभी लोगों की आवाजों को दबाने में आपका साथी बने और आपको अपना असली स्वरूप पाने से किसी को भी रोकने न दे। हमें उम्मीद है कि मंच का क्रंच एक प्रबल शक्ति बनकर उभरेगा और आज के किशोरों को लोगों की आलोचनाओं से आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने एवं सभी बाधाओं पर जीत हासिल करने के लिये प्रेरित करेगा। जयबीर अहमद, मैनेजिंग पार्टनर, नॉर्थ वीएमएल ने आगे कहा, "भारत के युवा एवं ऊर्जा से भरपूर कस्बों में सरल और अपनी सी लगने वाली कहानियों के माध्यम से, हमने दिखाया है कि कैसे मंच (शळ्ण्) का क्रंच किशोरों को अपनी अनूठी पहचान अपनाने और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।"

पांच बैंकों में एफडी पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज, नई दरें एक जुलाई से लागू

नई दिल्ली। एजेंसी

निजी क्षेत्र का एक्सिस बैंक अब तीन करोड़ रुपये के जमा पर 17-18 महीने की अवधि के लिए अपने ग्राहकों को 7.20 फीसदी ब्याज देगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.75 फीसदी है। दो साल की अवधि के एफडी पर 7.10 फीसदी ब्याज मिलेगा। बैंक सामान्य नागरिकों को एफडी पर तीन से 7.2 फीसदी के बीच ब्याज दे रहा है।वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 3.50 फीसदी से 7.75 फीसदी के बीच है।

बैंक एक जुलाई से अपने ग्राहकों को तीन करोड़ रुपये तक की एफडी पर 3.75 से लेकर 6.50 फीसदी तक ब्याज दे रहा है।वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर सर्वाधिक 8.75 फीसदी है, जो 0.50इ ज्यादा है।

बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, एक जुलाई से उसने भी एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव लागू कर दिया है। इसके तहत तीन करोड़ रुपये से कम के जमा पर बैंक अपने ग्राहकों को 15 महीने से दो साल की अवधि के लिए 7.20 फीसदी तक ब्याज देगा। एक साल की अवधि के जमा पर वह 6.7 फीसदी ब्याज दे रहा है। ब्याज की सबसे कम दर 3.50 फीसदी है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 7.75 फीसदी तक ब्याज देगा।

बैंक ऑफ इंडिया दे रहा 7.80 फीसदी तक ब्याज

बैंक ऑफ इंडिया की नई दरें 30 जून से लागू हैं। यह वरिष्ठ नागरिकों को 666 दिन की अवधि के लिए जमा पर 7.80 फीसदी तक ब्याज दे रहा है। सामान्य नागरिकों को 7.3 फीसदी ब्याज मिल रहा है। उधर, पंजाब एंड सिंध बैंक ने कहा कि उसकी भी संशोधित ब्याज दरें एक जुलाई से ही लागू हैं। यह अपने ग्राहकों 666 दिन के जमा पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.80 फीसदी ब्याज दे रहा है। सामान्य नागरिकों को यह 2.80 से 6.65 फीसदी तक ब्याज दे रहा है।

काम की खबर

बदल गए हैं मोबाइल पोर्ट और एनपीएस समेत पांच नियम पहले से हो जाएं सतर्क

नई दिल्ली। एजेंसी

क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मोबाइल पोर्ट और एनपीएस समेत पांच प्रमुख नियम एक जुलाई यानी सोमवार से बदल रहे हैं। दूरसंचार कंपनियां इसी महीने से मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट चलाना भी महंगा कर देंगी। इन बदलावों से सीधा आम आदमी की जेब पर असर पड़ने वाला है। एक जुलाई से सिम बदलने के बाद मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए अब सात दिन इंतजार करना होगा। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल फोन नंबर के जरिये होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पहले मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। अगर सिम बदलने की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के लिए अनुरोध किया गया है, तो इसे आवंटित नहीं किया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड बिलिंग

एक जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान से जुड़े नियम बदल गए हैं। इससे कुछ भुगतान एप के जरिये यूटिलिटी यानी बिजली और पानी जैसे बिल के भुगतान में दिक्कत आ सकती है। दरअसल, आरबीआई ने एक जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सिस्टम के जरिये भुगतान करने को कहा है। इसका मतलब है कि एक जुलाई से सभी बैंकों को भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिये ही बिल प्रोसेस करना होगा।

बंद हो जाएगा बैंक खाता

अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है और आपने उसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है तो वह एक जुलाई से काम नहीं करेगा। बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा है कि 30 अप्रैल, 2024 तक जिन खातों को इस्तेमाल किए हुए तीन साल से अधिक का समय हो गया है, ऐसे खाते को बैंक अब एक महीने के भीतर बंद कर देगा। बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए 30 जून, 2024 तक की डेडलाइन तय की थी।

एनपीएस : सौदे वाले दिन ही निपटान

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में अब सौदे वाले दिन ही निपटान हो जाया करेगा। यानी जिस दिन निवेश किया जाएगा, उसी दिन का मूल्य उनको मिलेगा। यह एक जुलाई से लागू होगा। 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक में निवेश आने पर नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी उसी दिन का माना जाएगा।अभी तक यह अगले दिन होता था।

महंगा हो जाएगा मोबाइल टैरिफ

जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने जुलाई से मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा कर दिया है। जियो और एयरटेल की मोबाइल दरें तीन जुलाई से महंगी हो जाएंगी। वोडाफोन आइडिया भी 4 जुलाई से टैरिफ महंगा कर देगा।

स्टार हैल्थ इंश्योरेंस ने 50 शहरों और कस्बों में अपनी होम हैल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराईं

इंदौर। एजेंसी

भारत की सबसे बड़ी रिटेल हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हैल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टार हैल्थ इंश्योरेंस) ने भारत के 50 से ज्यादा शहरों में अपनी होम हैल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। यह एक अत्यधिक व्यक्तिगत ग्राहक-केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके द्वार पर ही प्रभावशाली हैल्थकेयर समाधान और सुगम एवं तुरंत क्लेम सैटेलमेंट उपलब्ध कराना है। भारत में इन-होम मेडिकल केयर प्रदान करने के लिए स्टार हैल्थ इंश्योरेंस ने केयर24, पोर्टी, कॉलहैल्थ और अतुल्य होमकेयर जैसे अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ गठबंधन किया है।

स्टार हैल्थ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ, आनंद रॉय ने कहा, ''स्टार हैल्थ इंश्योरेंस में हमारा विश्वास है कि आज के ग्राहकों की

गुणवत्तापूर्ण हैल्थकेयर सेवाएं ग्राहकों के द्वार पहुँचाकर उनकी उपलब्धता बढ़ाई

विकसित होती हुई जरूरतों को पूरा करने में टेक्नोलॉजी मुख्य भूमिका निभाती है। होम हैल्थकेयर सर्विसेज़ का लॉन्च सुगम स्वास्थ्य सेवा समाधानों द्वारा ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ग्राहक अब स्टार हैल्थ मोबाईल ऐप द्वारा सुगमता से कई संक्रामक बीमारियों के लिए 100 प्रतिशत कैशलेस होम हैल्थकेयर सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।'' 140 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ भारत में स्वास्थ्य सेवा एक बड़ी चुनौती है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा के सीमित इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता कम है। स्टार हैल्थ इंश्योरेंस सुगम और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराके इस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 50 से ज्यादा शहरों में मौजूद हमारे ग्राहक हमें कॉल करके या स्टार हैल्थ मोबाईल ऐप द्वारा बुखार, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मूत्रनली के संक्रमण (यूटीआई) और एक्यूट गैस्ट्राइटिस जैसे संक्रामक बीमारियों का इलाज प्राप्त कर सकते हैं। इस गठबंधन द्वारा स्टार हैल्थ इंश्योरेंस प्राईमरी और क्रिटिकल केयर, इंटीग्रेटेड हैल्थकेयर सेवाओं, नर्सिंग, वृद्धों की केयर, फिज़ियोथेरेपी, शिशुओं की केयर, लैब डायग्नोस्टिक्स, और फार्मेसी की सेवाएं ग्राहकों के द्वार पर सुगमता से उपलब्ध कराएगा।

सैमसंग ने गैलेक्सी जेड सीरीज के अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग शुरू की

गुरुग्राम। एजेंसी

भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ब्राण्ड सैमसंग ने अब अपने उपभोक्ताओं के लिए गैलेक्सी जेड सीरीज के अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की प्री-बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है। इस तरह उपभोक्ताओं को खास ऑफर्स के साथ यह स्मार्टफोन जल्दी मिल सकेंगे।

ग्राहक Samsung.com, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, Amazon.in, Flipkart.com और भारत में अग्रणी रिटेल दुकानों पर 2000 रूपये की टोकन राशि देकर गैलेक्सी जेड सीरीज के अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को प्री-रिजर्व कर सकते हैं। गैलेक्सी जेड सीरीज के अगले स्मार्टफोन्स को प्री-रिजर्व करने वाले ग्राहकों को इन उत्पादों की खरीदी पर 7000 रूपये तक के फायदे भी मिलेंगे।

सैमसंग ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि वह 10 जुलाई को अपने ग्लोबल इवेंट में नेक्स्ट जनरेशन के गैलेक्सी जेड सीरीज स्मार्टफोन्स एवं इकोसिस्टम डिवाइसेस लॉन्च करेगा। अपने एक वक्तव्य में सैमसंग ने कहा कि गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट का आयोजन पेरिस में होगा। वहां संस्कृतियों का प्रसिद्ध संगम-बिन्दु और प्रचलनों का केन्द्र हमारे नये एवं अत्याधुनिक नवाचारों की पेशकश का सबसे बढ़िया परिदृश्य देगा।

कंपनी ने आगे कहा कि, ''गैलेक्सी एआई का अगला मोर्चा खुल रहा है। अब नई गैलेक्सी जेड सीरीज और और गैलेक्सी के पूरे इकोसिस्टम में भी गैलेक्सी एआई की ताकत को जानने के लिये तैयार हो जाइये। संभावनाओं की दुनिया में जाने की तैयारी कर लीजिये, क्योंकि हम मोबाइल एआई के नये फेज़ में कदम रख रहे हैं।''

सैमसंग इंडिया ने अगले सैमसंग गैलेक्सी वियरेबल और हीयरेबल डिवाइसेस के लिये भी प्रि-बुकिंग कराने की घोषणा कर दी है। ग्राहक 1999 रूपये की टोकन राशि में सैमसंग के गैलेक्सी इकोसिस्टम के अगले उत्पादों को पहले से बुक करा सकते हैं। इन उत्पादों की खरीदी पर उन्हें 6499 रूपये तक के फायदे भी मिलेंगे।

एनसीईआर के शोध पत्र में जताया गया अनुमान

बीते 12 वर्षों में 12 फीसदी से ज्यादा घटी गरीबी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में बीते कुछ वर्षों में गरीबी कम होने के संकेत मिले हैं। आर्थिक मामलों के थिंक टैंक एनसीएईआर के एक शोध पत्र के अनुसार महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत में गरीबी 2011-12 के 21.2 प्रतिशत से घटकर 2022-24 में 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

एनसीएईआर (नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च) के सोनाल्दे देसाई की ओर से लिखे गए पेपर 'रिथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट्स इन ए चेंजिंग सोसाइटी' में भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस) के वेव 3 के डेटा के साथ-साथ आईएचडीएस के वेव्स 1 और वेव्स 2 के डेटा का उपयोग किया गया है। आईएचडीएस के निष्कर्षों के अनुसार ... 2004-2005 और 2011-12 के बीच गरीबी में काफी गिरावट आई (38.6 से 21.2 के प्रति व्यक्ति अनुपात से) और महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद 2011-12 और 2022-24 (21.2 से 8.5) के बीच इसमें गिरावट जारी रही।' दस्तावेज में कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि और गरीबी में गिरावट एक गतिशील माहौल बनाती है जिसके लिए फुर्तीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की जरूरत होती है।

दस्तावेज में कहा गया है कि सामाजिक बदलाव की गति के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां चलना भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती होगी क्योंकि यह देश सभी के लिए समान विकास का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है। पेपर के अनुसार, आर्थिक विकास के युग के दौरान, जब अवसर बढ़ते हैं, गरीबी के दीर्घकालिक निर्धारक घट सकते हैं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी और मृत्यु से जुड़े जीवन की दुर्घटनाएं, और व्यवसाय-विशिष्ट अवसरों में परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इस साल की शुरुआत में नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा था कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी घटकर पांच प्रतिशत रह गई है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अगर हम गरीबी रेखा को देखें और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के साथ बढ़ाकर आज की दर पर लाएं तो हम पाएंगे कि सबसे कम आंशिक, 0-5 फीसदी की औसत खपत लगभग समान है। इसका मतलब है कि देश में गरीबी केवल 0-5 प्रतिशत के समूह में है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने 24 फरवरी को वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय पर डेटा जारी किया था, जिसमें प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुने से अधिक दिखाया गया।

तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित गरीबी रेखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 447 रुपये और 579 रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन 2004-2005 के दौरान राज्यों के बीच स्थिति भिन्न थी। इन गरीबी सीमाओं को बाद में योजना आयोग की ओर से 2011-12 के लिए 860 रुपये और 1,000 रुपये तक समायोजित किया गया था।

सीएम मोहन बोले-
बजट की थीम- 'विकसित भारत-विकसित मध्य प्रदेश', नहीं लगाया कोई टैक्स

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पहली बार तीन लाख 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि का बजट पेश किया गया है। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। किसी भी विभाग की राशि को कम नहीं किया है। सभी विभागों की राशि बढ़ाई है। 'विकसित भारत-विकसित मध्य प्रदेश' की थीम पर पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षा अनुसार जीडीपी की ग्रोथ को सुनिश्चित किया गया है। अगले पांच साल में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विद्यार्थी छात्रावासों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए बजट में पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की गई है। गौ-शालाओं के लिए भी पर्याप्त राशि है। औद्योगिक विकास का बजट 40 प्रतिशत बढ़ाया है। भारी उद्योग, एमएसएमई और कुटीर उद्योग सहित स्व-सहायता समूह के लिए भी बड़ी राशि रखी है। स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, एक्सप्रेस-वे पर विशेष ध्यान होगा। महाकौशल, चंबल, विंध्य, मालवा, आदि की सीधी कनेक्टिविटी राजधानी से जुड़े, इस उद्देश्य से पर्याप्त व्यवस्था करते हुए वित्तीय तरलता का प्रावधान किया गया है।

सिंहस्थ की तैयारियों का श्री गणेश

बजट में सिंहस्थ-2028 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए नई बजट लाइन खोली गई है। सिंहस्थ कार्ययोजना के तहत 15 विभागों के कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंहस्थ की तैयारी को उच्च गुणवत्ता एवं विशेषज्ञों के साथ बनाने के लिए तथा तकनीक और आईटी का सहारा लिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए विशेषज्ञ नियुक्त होंगे। इसके लिए पांच करोड़ रुपये रखे गए हैं।

विपक्ष के वॉकआउट के बीच वित्त मंत्री ने बजट किया पेश
3.65 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

मध्य प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश कर दिया है. इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार बजट को लेकर उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दिए, जबकि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर जमकर बिंदु उठाएं. इस दौरान कई बार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को शांत करने की कोशिश भी की.

भोपाल। एजेंसी

मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग को बड़ा लाभ देने का दावा कर रही है. दूसरी तरफ विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का कहना है कि नर्सिंग घोटाले पर लगे सवालों का जवाब न देना पड़े, इसी के चलते 3 जुलाई को सरकार ने बजट पेश किया है. हालांकि मध्य प्रदेश की जनता को इस बजट में केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है. उमंग सिंघार का कहना है कि वे पहले ही इस बात को कह चुके थे कि 3 जुलाई को ही सरकार बजट पेश करेगी.

सरकार का कहना है कि प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई. मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए. आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस -वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है.

मोहन सरकार का बजट अलर्ट

मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है।

हवाई सुविधा बनेगी और सुगम

इस बजट में रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा। बजट में संस्कृति विभाग के लिये 1 हजार 81 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना ज्यादा है। वहीं प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जोकि एक कीर्तिमान है। साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएम श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है।

6 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें

मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। जिनमें भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन, सागर शामिल है।

ऊर्जा के लिए 19000 करोड़

सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। साथ ही दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।

हमारे फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था पर असर
CBDT प्रमुख ने आयकर अधिकारियों को लिखा खत, पदभार संभाल की ये अपील

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नवनियुक्त चेयरमैन रवि अग्रवाल ने आयकर विभाग के अधिकारियों से कहा है कि उनके द्वारा लिए गए फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था, कारोबार सुगमता और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर असर होगा। अग्रवाल (59) ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में प्रत्यक्ष कर विभाग के प्रशासनिक निकाय के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। सरकार ने पिछले सप्ताह उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे।

सीबीडीटी के नए प्रमुख ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दो पेज का पत्र लिखा। पीटीआई के अनुसार उन्होंने पत्र में लिखा, 'हमें मिलकर एक पेशेवर विभाग बनाना चाहिए जो जांच की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ हो, करदाताओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो, प्रौद्योगिकी का जानकार हो और करदाताओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण से अवगत हो।' अग्रवाल ने सोमवार को जारी अपने संदेश में कहा, 'हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो निर्णय लिए हैं उनका असर देश की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और कारोबार सहित व्यापार करने में आसानी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्येक विभाग को 100 दिन की कार्य योजना बनाने के लिए अनिवार्य किया है और इसलिए, वह विभागों से उम्मीद करते हैं कि वे अपनी 100-दिवसीय कार्य योजनाएं तैयार करें और समयबद्ध तरीके से पहल करें।'

नए सीबीडीटी चीफ ने कहा, 'इन योजनाओं को प्रत्येक रेंज, चार्ज और क्षेत्र में उपयुक्त रूप से तैयार और कार्यान्वित किया जा सकता है। कृपया याद रखें कि आयकर विभाग की उपलब्धियां एक सामूहिक प्रयास है और प्रत्येक स्तर पर की गई पहल विभाग की उपलब्धियों को जोड़ती है।'

उन्होंने विभाग को अपने संदेश में लिखा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों और शुल्कों की लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाएं। मैं आपके द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के बारे में संबंधित टीमों के साथ चर्चा करने की सराहना करूंगा।'

अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय लेनदेन की जटिलताएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और वित्तीय लेनदेन की प्रकृति भी विकसित हो रही है। हम करदाताओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को संबोधित करते हैं जो नए व्यक्तिगत करदाताओं से लेकर दुनिया भर में संचालन करने वाले संगठनों तक हैं। उन्होंने लिखा, 'आइए हम व्यवसायों और वित्तीय लेनदेन में नवीनतम रुझानों को समझने के साथ खुद को लैस करें ताकि हम पेशेवर दृष्टिकोण के साथ संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम हों।'

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारियों को वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए हितधारकों के साथ 'जुड़ना' चाहिए और दूसरी तरफ हमारी प्रक्रियाओं में अपना विश्वास बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमें अपनी प्रक्रियाओं में अधिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी प्रक्रियाएं कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी हों, जिससे करदाताओं के बीच भरोसा और विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा, 'आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने से हमें संचालन को सुव्यवस्थित करने, अक्षमताओं को कम करने और करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिली है।

अग्रवाल ने कहा कि जहां प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं, सरकारी प्रक्रिया में बदलाव और हितधारकों से जुड़ाव के जरिए हासिल की गई उपलब्धियों पर हमें गर्व है, वहीं हमें यह समझना होगा कि अभी भी कई क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीबीडीटी और कर विभाग आठ करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वालों तथा करीब 34 लाख कर कटौती करवाने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रक्रिया लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टाटा मैजिक बाइ-फ्यूल ने इंदौर में अंतिम मील तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाया

इंदौर। एजेंसी

टाटा मैजिक ने शहर की व्यस्त गलियों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, देश में लाखों यात्रियों को उनके ठिकानों तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल की है। अब हाल ही में लॉन्च हुई टाटा मैजिक बाइ-फ्यूल लोगों की यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए तैयार है। इस वाहन में 60 लीटर का सीएनजी टैंक और 5 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है। यह एक बार ईंधन भरने पर लगभग 300 किलोमीटर की कुल रेंज देता है। ऐसे में यह लंबी दूरियों और तरह-तरह के क्षेत्रों के लिये आदर्श है। यह अभिनव वैरिएंट सीएनजी और पेट्रोल के बीच आसानी से अदला-बदली कर सकता है, ताकि समय की बचत हो और ईंधन की खपत कम हो।

टाटा मैजिक बाइ-फ्यूल यात्रियों के साथ-साथ ड्राइवरों की भी बदलती जरूरतें पूरी करता है। अपने सेगमेंट में इसके पास 9 लोगोंं ड्राइवर के बैठने की सर्वोच्च क्षमता है। इसकी खूबियों में रेडियल टायर, गियरशिफ्ट एडवाइजर और ड्राइवर के लिये बेहतर एर्गोनॉमिक्स शामिल हैं। यह वाहन ईंधन की खपत को सटीक रखता है और इसलिये इसके स्वामित्व में कम खर्च आता है। दो साल या 72,000 किलोमीटर की बेजोड़ वारंटी के साथ, टाटा मैजिक बाइ-फ्यूल भरोसेमंद एवं टिकाऊ वाहनों की पेशकश के लिये कंपनी के वादे को दोहराता है। यह फ्लीट के मालिकों और निजी ऑपरेटरों को समान रूप से मानसिक शांति देता है।

शुभ काम की शुरुआत दही से क्यों, दही को क्यों माना जाता है पवित्र सामग्री, जानें रहस्य

दही, दूध, शहद ऐसी सामग्रियाँ हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखती है। यह न केवल एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है, बल्कि पूजा-पाठ से लेकर किसी भी शुभ काम की शुरुआत तक के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार दही को भी बहुत शुभ माना जाता है, कई जगह तो यह भी माना जाता है कि इसके इस्तेमाल से ही किसी भी कार्य में शुद्धि आती है। इसी वजह से किसी भी काम में शुभता लाने के लिए दही का प्रयोग करते हैं। यही नहीं जब कोई व्यक्ति किसी भी काम की शुरुआत करता है या कहीं बाहर जाता है तो उसे सदियों से घर से बाहर निकलते समय दही के साथ चीनी खिलाने की परंपरा है। जाने इसका महत्व।

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

दही का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

भारत की समृद्ध धार्मिक परंपराओं में दही का उपयोग प्राचीन काल से ही विभिन्न स्थानों पर होता चला आया है। इसे पवित्रता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से दही को कई ऐसी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाता है जो पूजा-पाठ से जुड़ी होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में दही को ग्रहों की शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

दही को भगवान की प्रिय सामग्री माना गया है

दही भगवान कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय है। उनके बाल रूप की कथाओं में वो मक्खन और दही चोरी करने वाले 'माखन चोर' के रूप में जाने जाते हैं। इस कारण दही का उपयोग आज भी उनकी पूजा में विशेष महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को दही से स्नान कराने या दही का भोग लगाने से उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। दही का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। भारतीय समाज में दही को पवित्र और शुभ माना जाता है। विभिन्न धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। दही को प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा भी प्रचलित है, जो इसे धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा बनाती है।

जानें क्यों दही से ही की जाती है शुभ कार्यों की शुरुआत

किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, या किसी नए काम की शुरुआत जैसे नई नौकरी में दही का सेवन करके आरंभ करना शुभ माना जाता है। इसे 'दही-चीनी' के रूप में दिया जाता है, जोकि शुद्धता और मिठास का प्रतीक है। यह प्रथा सफलता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी यात्रा के पहले भी दही-चीनीका सेवन करने से यात्रा शुभ और सुरक्षित हो जाती है। इसे एक तरह से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के रूप में देखा जाता है।

ग्रहों को मजबूत करता है दही

ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और इसका संबंध शांति, सौम्यता और मानसिक संतुलन से होता है। चंद्रमा की शांति के लिए दही का सेवन और उसका दान करना शुभ माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको सोमवार के दिन दही का सेवन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है।

कुछ विशेष ग्रह दोषों, जैसे कि राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए भी दही का उपयोग किया जाता है। राहु की शांति के लिए, काले तिल और दही का दान करना लाभकारी माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में शांति और स्थिरता आती है। शुक्र ग्रह का संबंध सुख-सुविधाओं और समृद्धि से है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दही का सेवन और दान करना शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन दही का सेवन और व्रत करना शुक्र को प्रसन्न करता है और जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में आनंद लाता है। इस तरह से दही का इस्तेमाल किसी भी शुभ काम में करने से सफलता का आशीर्वाद मिलता है।

जानें किस दिशा में करें सूर्य यंत्र की स्थापना

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

वास्तु शास्त्र में यंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। इन यंत्रों को स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यंत्रों को विभिन्न धातुओं, रत्नों और मंत्रों से निर्मित किया जाता है। इनका उपयोग घरों, कार्यालयों और अन्य स्थानों में स्थापित करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। घर लाएं सूर्य यंत्र, आपकी सफलता के घोड़े कभी रूकेंगे नहीं

वहीं ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह दोष है, तो यंत्रों का उपयोग करके उन दोषों को दूर किया जा सकता है। बता दे, यंत्रों को स्थापित करने से व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। यंत्रों को स्थापित करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। यंत्रों को स्थापित करने से मन को शांति मिलती है।

घर की किस दिशा में स्थापित करें सूर्य यंत्र?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्य यंत्र को घर की पूर्व दिशा में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा होती है और इसे ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इससे सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन में मान-सम्मान, यश और सकारात्मकता का भी संचार होता है।

सूर्य यंत्र स्थापित करने के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

यंत्र को दीवार पर इस तरह से स्थापित करें कि उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो।

यंत्र को किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करें, जैसे कि पूजा की जगह या लिविंग रूम।

यंत्र को स्थापित करने से पहले उसकी अच्छी तरह से सफाई कर लें।

यंत्र को स्थापित करते समय मंत्रों का जाप करें।

यंत्र को स्थापित करने के बाद उसकी नियमित रूप से पूजा करें।

सूर्य यंत्र स्थापित करने के लाभ

घर में सूर्य यंत्र स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आता है। यह स्वास्थ्य और सफलता को बढ़ावा देता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह आत्मविश्वास और एकाग्रता में सुधार करता है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है। साथ ही व्यक्ति को मान-सम्मान की भी प्राप्ति होती है।

सूर्य यंत्र की पूजा विधि

सूर्य यंत्र की पूजा करने के लिए, पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। यंत्र को एक साफ कपड़े पर रखें। यंत्र के पास एक दीपक जलाएं और धूप जलाएं। भगवान सूर्य का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें।

सूर्य यंत्र की पूजा करने के दौरान मंत्र जाप

अगर आप सूर्य यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, तो इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। इससे लाभ हो सकता है।

'ॐ सूर्याय नमः'
'ॐ गुरुभ्यो नमः'
'ॐ आदित्याय नमः'।

शास्त्रों में ठोकर लगे पानी को क्यों माना गया है अशुभ, जानिए

पंडित कपिल पाराशर
बनारस वाले ज्योतिष
आचार्य वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

शास्त्रों से जुड़ी ऐसी कई धार्मिक मान्यताएं हैं जिनके बारे में अक्सर आपने सुना ही होगा, पैर हिलाना, ठोकर लगे पानी को नहीं पीना, रात में बालो को खुला नहीं रखना इनसब के लिए घर में भी टोका जाता है। ऐसी ही एक मान्यता है कि ठोकर लगा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि अगर पानी की बोतल या गिलास पर पैर लग जाए तो उस पानी को नहीं पीना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का पानी पीने से न सिर्फ अशुभता जीवन में आती है बल्कि स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है।

क्यों नहीं पीना चाहिए ठोकर लगा पानी

शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस भी वस्तु को ठोकर लग जाए वह राहु के हिस्से चली जाती है। एस एमें उस वस्तु का इस्तेमाल करने से राहु का बुरा असर उस व्यक्ति पर दिखने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर पीने के पानी पर पैर की ठोकर लग जाए तो उस पानी को नहीं पानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर उस पानी को पिया जाए तो उससे नकारात्मकता शरीर में प्रवेश करती है।

इतना ही नहीं, उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके शरीर में बदलाव आने लगते हैं, या तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है या आपको भारी तनाव महसूस होना शुरूहो जाता है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण आपकी मानसिक शांति भंग होती है और यहान कि आपके शरीर में अजीब से थकान जन्म लेने लगती है जिसकी वजह से आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं। ठोकर लगा पानी इसलिए भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पानी को पीने से आप राहु की अशुभता को स्वीकार करते हो, जिसके कारण अन्य ग्रह अशांत हो जाते हैं।

जानिए कब हैं आषाढ़ अमावस्या जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं
रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व माना जाता हैं। पंचांग के अनुसार, साल में कुल 12 अमावस्या तिथियां पड़ती हैं। हर अमावस्या तिथि का माह के अनुसार महत्व होता हैं। इन्हीं में से एक है आषाढ़ अमावस्या। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष दूर होता हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता हैं।

आषाढ़ अमावस्या कब

आषाढ़ अमावस्या तिथि का शुभारंभ 5 जुलाई, दिन शुक्रवार को सुबह 4 बजकर 57 मिनट से होगा। वहीं, इसका समापन 6 जुलाई, दिन शनिवार को सुबह 4 बजकर 26 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई को पड़ेगी।

आषाढ़ अमावस्या का पूजा मुहूर्त

आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 12 मिनट से 5 बजकर 26 मिनट तक का हैं। वहीं, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 12 मिनट से 6 बजकर 21 मिनट तक का हैं। इसके अलावा, पितृ तर्पण सुबह 11 बजे तक कर सकते हैं।

आषाढ़ अमावस्या का महत्व

आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किया गया दान बहुत लाभकारी माना जाता हैं। मान्यता हैं कि पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अपनी कृपा बरसाते हैं और उनके आशीर्वाद से पारिवारिक शांति बनी रहती है। इसके अलावा, गंगा स्नान का भी खासा महत्व हैं।

अब नहीं चलेगा अंग्रेजों के जमाने का कानून

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू

नई दिल्ली। एजेंसी

पहली जुलाई से काफी कुछ बदल गया है. खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी. इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम-कायदे बदल जाएंगे. इनमें कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई हैं तो कुछ धाराओ में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई हैं. नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा.

कोर्ट से किसी अपराध में 100 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती. हालांकि, अगर किसी और सजा के साथ-साथ भी यही सजा मिलती है तो फिर इसे चुनौती दी जा सकती है।

कैदियों के लिए क्या कुछ बदला?

जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या के बोझ को कम करने के मकसद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बड़ा बदलाव किया गया है. कानून की धारा 479 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी एक तिहाई से ज्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है. हालांकि, ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी. ऐसे कैदियों को जमानत नहीं दी जाएगी, जिन्होंने उम्रकैद की सजा वाले अपराध किए हों. इसके अलावा सजा माफी को लेकर भी बदलाव किया गया है।

अगर किसी कैदी को सजा-ए-मौत मिली हो तो उसे उम्रकैद में बदला जा सकता है. इसी तरह उम्रकैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है. साथ ही जिन दोषियों को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा मिली होगी, उनकी सजा को 3 साल की जेल में बदला जा सकता है. जबकि, 7 साल या उससे कम की सजा वाले दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल अहम बदलाव

CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थीं वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं हैं. इसमें ऑडियो-विडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है. वहीं, नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉण्ड पर रिहा करने का प्रावधान है. कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो FIR दर्ज करा सकेगा. FIR होने के 15 दिनों के भीतर उसे ओरिजिनल जूरिडिक्शन यानी जहां का मामला है वहां भेजना होगा. पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन में संबंधित अथॉरिटी से इजाजत मिलेगी. अगर नहीं मिली तो उसे ही सेंक्शन मान लिया जाएगा।

FIR के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट

FIR के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट दाखिल करनी होगी. चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे. इसके साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होगा. जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी. पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा. ऑफलाइन, ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी. 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले मामले में विक्टिम को सुने बिना वापस नहीं किया जाएगा.थाने में कोई महिला सिपाही भी है तो उसके सामने पीड़िता के बयान दर्ज कर पुलिस को कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी।

किन मामलों में नहीं कर सकेंगे अपील?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा मिलने पर ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती. अगर हाईकोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. आईपीसी में धारा 376 थी, जिसके तहत 6 महीने से कम की सजा को चुनौती नहीं दे सकते थे. यानी, नए कानून में थोड़ी राहत दी गई है।

इसके अलावा, अगर सेशन कोर्ट से किसी दोषी को तीन महीने या उससे कम की जेल या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे भी चुनौती नहीं दे सकते. वहीं, अगर मजिस्ट्रेट

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या हुए जरूरी बदलाव

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) में कुल 170 धाराएं हैं. अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थीं. नए कानून में 6 धाराओं को निरस्त किया गया है. इसमें 2 नई धाराएं और 6 उप-धाराओं को जोड़ा गया है. गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है. तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कोर्ट में मान्य होंगे. इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन और वॉइस मेल जैसे रिकॉर्ड भी शामिल हैं.

महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध

महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों में धारा 63-99 तक रखा गया है. अब दुष्कर्म को धारा 63 से परिभाषित किया गया है. रेप की सजा को धारा 64 में बताया गया है. इसके साथ ही गैंगरेप के लिए धारा 70 है. सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध धारा 74 में परिभाषित किया गया है. नाबालिग से रेप के मामले या गैंगरेप के मामले में अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है. धारा 77 में स्टॉकिंग को परिभाषित किया गया है, वहीं दहेज हत्या धारा-79 में और दहेज- प्रताड़ना धारा-84 में बताया गया है. शादी का झांसा या वादा कर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध बनाया गया है यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है.

नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में सजा में सख्ती

बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है. 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी. बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है. इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

कत्ल को इस तरह किया गया है परिभाषित

सबसे बड़ी बात, सरकार ने मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा है. शरीर पर चोट करने वाले अपराधों को धारा 100-146 तक परिभाषित किया गया है. मर्डर के लिए सजा धारा 103 में बताई गई है. धारा 111 में संगठित अपराध में सजा का प्रावधान है. धारा 113 में टेरर ऐक्ट बताया गया है. मॉब लिंचिंग मामले में भी 7 साल कैद या उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रावधान है.

मैरिटल रेप के लिए क्या?

18 वर्ष से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाए जाते हैं तो वह रेप नहीं माना जाएगा. शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप की कैटिगरी से बाहर कर दिया गया है. इसे धारा 69 में अलग से अपराध बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई शादी का वादा कर संबंध बनाता है और वह वादा पूरा करने की मंशा नहीं रखता है या फिर नौकरी का वादा कर या प्रमोशन का वादा कर संबंध बनाता है तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल कैद की सजा हो सकती है. IPC में यह रेप के दायरे में था.

राजद्रोह की धारा नहीं

भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है. IPC 124A राजद्रोह का कानून है. नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने के खिलाफ जैसे मामलों को धारा 147-158 में परिभाषित किया गया है. धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्रकैद होगी. धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्रकैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है. धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर लिखकर या बोलकर या संकेतों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है, जिससे कि विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो या अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता हो तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद या फिर 7 साल की सजा है.

☐ **मेंटल हेल्थ :** मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने क्रूरता माना गया है. इसे धारा 85 में रखा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कार्रवाई होती है, तो वह क्रूरता के दायके में आएगी. अगर महिला को चोट पहुंचाई जाती है या उसके जीवन को खतरा होता है तो या फिर हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ को खतरे में जाता है तो दोषी को 3 साल की सजा मिलने का प्रावधान है.

☐ **संगठित अपराधः** इन्हें धारा 111 में रखा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, जबरन वसूली करता है या आर्थिक अपराध करता है तो दोषी को फांसी या उम्रकैद हो सकती है.

☐ **चुनावी अपराध की धाराः** चुनावी अपराध को धारा 169-177 तक रखा गया है. संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट, डकैती आदि मामले को धारा 303-334 तक रखा गया है. मानहानि का ज़िक्र धारा 356 में है.

☐ **धारा 377:** नए बिल में धारा 377 यानी अप्राकृतिक यौनाचार को लेकर कोई प्रावधान साफ नहीं किए गए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था. महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार रेप के दायरे में हैं. लेकिन बालिग पुरुष की मर्जी के खिलाफ और पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौनाचार पर बिल में प्रावधान नहीं है.

नए कानूनों में क्या है आतंकवाद?

अब तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी परिभाषा है. इस कारण अब कौनसा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा, ये निश्चित हो गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के मुताबिक, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा.

आतंकी कृत्य में क्या-क्या जोड़ा?

आतंकवाद की परिभाषा में 'आर्थिक सुरक्षा' शब्द को भी जोड़ा गया है. इसके तहत, अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा. इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा. नए कानून के मुताबिक, बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसमें किसी की मौत या चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य में गिना जाएगा.

आतंकी गतिविधि से कमाई भी आतंकवाद

इसके अलावा देश के अंदर या विदेश में स्थित भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संपत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना भी आतंकवाद के दायरे में आएगा. अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि कोई संपत्ति आतंकी गतिविधि के जरिए कमाई गई है, उसके बावजूद वो उस पर अपना कब्जा रखता है, तो इसे भी आतंकी कृत्य माना जाएगा.

क्रेडिट एक्सेस इंडिया फाउंडेशन ने उद्योगवर्धिनी शिक्षण संस्था के साथ गठबंधन किया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई), क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण लिमिटेड की सीएसआर विंग, क्रेडिटएक्सेस इंडिया फाउंडेशन ने उद्योगवर्धिनी शिक्षण संस्था के साथ एक समझौतापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 200 वंचित महिलाओं और युवाओं को आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस 10 माह के प्रोजेक्ट का पहला चरण इंदौर जिले से शुरू होगा, जिसके बाद इसे उज्जैन जिले में ले जाया जाएगा। ये दोनों संस्थाएं मिलकर इंदौर और उज्जैन में वंचित और कमजोर समुदायों के लिए विभिन्न कौशल प्रशिक्षण के सत्र चलाएंगी और उन्हें रोजगार के अवसरों एवं स्वरोजगार में सहयोग प्रदान करेंगी।

इस कार्यक्रम के बारे में श्री गणेश नारायणन, चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर, सीए ग्रामीण, एवं डायरेक्टर सीएआईएफ ने कहा यूएसएस के साथ हमारे सहयोग के अंतर्गत हम ग्रामीण युवाओं को बहुमूल्य कौशल प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि इसका लाभ न केवल उन्हें मिले, बल्कि समुदायों के संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान मिल सके। इस साझेदारी से आर्थिक सशक्तिकरण लाने और ग्रामीण भारत में जीवन स्तर बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।'' श्री श्रीराम चंडक, चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर, यूएसएस ने कहा हमारी तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में हम वंचित समुदायों को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो न केवल इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों, बल्कि इसके द्वारा होने वाले विकास का नेतृत्व भी करें। उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर और उन्हें कौशल प्रदान करके सस्टेनेबल आजीविका निर्माण में समर्थ बनाकर हमारा उद्देश्य उन्हें प्रगति के सफर में शामिल करना है। हमें अपना यह उद्देश्य पूरा करने के लिए सीए इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी करने पर गर्व है।'' यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विषयों में क्लासरूम सत्र और ऑन-द-जॉब अनुभव प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उद्योग के लिए तैयार करने और उनके प्रशिक्षण का अनुभव बेहतर बनाने के लिए कार्यशालाओं, गेस्ट लेक्चर्स का आयोजन किया जाएगा और नजदीकी अस्पतालों एवं उद्योगों में उन्हें प्लेसमेंट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थियों के विकास एवं उनके करियर की प्रगति को मॉनिटर किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो सीखे गए कौशल के साथ अपना व्यवसायिक विकास कर सकें।

OPPO ने 17,999 रुपये में A3 Pro पेश किया, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी के नए मानक स्थापित

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

OPPO इंडिया ने OPPO A3 Pro के लॉन्च की घोषणा की है, जो प्रीमियम डिज़ाईन के साथ ऑल-राउंड एंड्योरेंस के लिए तैयार किया गया है। इस नए ए-सीरीज़ स्मार्टफोन में ड्रॉप एवं इंपैक्ट रज़िस्टैंस के लिए डैमेजप्रूफ ऑल-राउंड आर्मर बॉडी, पानी एवं धूल के रज़िस्टैंस के लिए आईपी54 सर्टिफिकेशन, और गीले हाथों से उपयोग के लिए स्प्लैश टच टेक्नोलॉजी है। इसमें 120हर्ट्ज़ अल्ट्रा ब्राईट डिस्प्ले, एआई लिंकबूस्ट, एआई इरेज़र, और 5100 एमएएच की शक्तिशाली आईपर एनर्जी बैटरी लगी है, जो 45 वॉट के सुपरवूक फ्लैश चार्ज और चार साल से ज्यादा लंबी उम्र के साथ आती है।

अत्यधिक विश्वसनीयता और ड्यूरेबिलिटी OPPO A3 Pro की डैमेजप्रूफ ऑल-राउंड आर्मर बॉडी में मजबूत आंतरिक संरचना और अनेक ड्रॉप रज़िस्टैंट सामग्री, जैसे स्क्रीन कवर के लिए ब्लू ग्लास डबल टैंपर्ड ग्लास है, जो फोन को रोजमर्रा के धक्कों और टूट-फूट से सुरक्षा प्रदान करता है। फोन के आंतरिक पुर्जों को धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके चारों ओर बायोमिमेटिक स्पंज का गद्दा बनाया गया है। A3 Proको अपनी अत्यधिक मजबूती के लिए एसजीएस ड्रॉप-रज़िस्टैंस सर्टिफिकेशन (स्टैंडर्ड) और एसजीएस मिलिटरी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। गिरने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए OPPO A3 Proबॉक्स में नए डिज़ाईन के एंटी-ड्रॉप शील्ड केस के साथ आता है। OPPO लैब्स में किए गए परीक्षणों में यह डिवाईस टंबल ड्रम में 450 रोटेशन तक सुरक्षित पाई गई, जिससे बिना केस की तुलना में इसके 200 प्रतिशत ज्यादा सुरक्षित होने का प्रदर्शन होता है।

द कोका-कोला कंपनी की ऑनेस्ट टी ने लॉन्च किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ऑनेस्ट टी, ऑर्गेनिक ग्रीन टी से बनाया गया एक रेडी टु ड्रिंक बेवरेज है। इसने मशहूर लेखिका, स्तंभकार एवं वेलनेस की शौकीन ट्विंकल खन्ना के साथ मिलकर अपना नया कैम्पेन #FindYourGood शुरू किया है। नई फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ट्विंकल खन्ना को रोजमर्रा की कश्मकश के बीच क्ष्वहोर्ज़ी पीने से राहत मिलती है। इसे ऑर्गेनिक ग्रीन टी से बनाया गया है, जो प्रसिद्ध मकाइबारी टी स्टेट से मंगाई गई है।

सामाजिक अपेक्षाओं से भरी इस दुनिया में ऑनेस्ट टी का कैम्पेन लोगों को राहत पाने का अपना खुद का तरीका तय करने के लिये प्रेरित करता है। ब्राण्ड इस तलाश में लोगों का एक सच्चा साथी बनकर उभरा है और इसने दो बेहतरीन फ्लेवर्स - लेमन-तुलसी और मैंगो की पेशकश की है।

कैम्पेन को शुरू करने के लिये, ऑनेस्ट टी द्वारा सोशल फिल्मों और डिजिटल एक्टिवेशंस की शुरूआत की जाएगी। यह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उपभोक्ताओं से जुड़ेगा। कैम्पेन फिल्म की परिकल्पना डब्ल्यूपीपी ओपन एक्स ने की है। इस फिल्म में हमारे लिये एक प्रासंगिक पल आता है, जब ट्विंकल अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहती हैं। जब वह आराम करने के लिये बैठती हैं, तब ऑनेस्ट टी का एक घूंट पीकर कहती हैं ''यह आपको ही तय करना है कि आपके लिये अच्छा क्या है''।

ऑनेस्ट टी के साथ जुड़ने के बारे में ट्विंकल खन्ना ने कहा, ''मैं #FindYourGood कैम्पेन का हिस्सा बनकर उत्साहित हूँ, क्योंकि यह एक अच्छी और संपूर्ण जिन्दगी के लिये मेरे मंत्र से मेल खाता है। रोजाना की जिन्दगी में खुशी और संतुलन लाने के महत्व से प्रेरित होकर, ऑनेस्ट टी का कैम्पेन आधुनिक महिलाओं की सेहत में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेगा।''

Zupee ने लूडो के सदाबहार आकर्षण का जश्न मनाते हुए पेश किया सदियों से इंडिया का अपना गेम अभियान

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के सबसे बड़े कौशल-आधारित लूडो प्लेटफॉर्म Zupee ने अपना ताज़ातरीन विज्ञापन अभियान सदियों से इंडिया का अपना गेम पेश किया है, जो भारत के सबसे प्रिय बोर्ड गेम, लूडो के सदाबहार आकर्षण को ज़ाहिर करता है। यह अभियान सिर्फ लॉन्च नहीं, बल्कि एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो आकर्षक तरीके और हास्य के साथ कई सदियों में हुए लूडो के विकास को रचनात्मक रूप से दर्शाती है, जो ज़ूपी पर इसके आधुनिक कौशल-आधारित अवतार में परिणत होती है। प्राचीन पाषाण युग से लेकर शाही दरबारों की भव्यता तक, ब्लैक एंड व्हाइट रंग के सुनहरे युग और शानदार रेट्रो युग तक, Zupee का अभियान रचनात्मक रूप से लूडो की निरंतर यात्रा को दर्शाता है। यह कौशल-आधारित विविधताओं की पेशकश करने में Zupee के नवोन्मेष को भी रेखांकित करता है जो खिलाड़ियों को आज के डिजिटल युग में Zupee लूडो पर कैश रिवॉर्ड्स जीतने में भी मदद करता है, जो पहले के मुकाबले बिलकुल अलग जब इसके लिए कोई ठीक-ठाक पुरस्कार नहीं मिलते थे। इस अभियान में सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, मौनी रॉय, विजय राज और अभय देओल सहित कई सितारों को दिखाया गया है, जिनमें से सभी मशहूर अभिनेता अलग-अलग युग को दर्शाते हैं, जो इस विचार को दर्शाता है कि लूडो वास्तव में रचनात्मकता के लिहाज़ से सदियों से इंडिया का अपना गेम है।

हीरो मोटोकॉर्प ने कलेक्टर्स एडिशन मोटरसाइकिल - 'द सेंटेनियल' को लॉन्च किया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

'मेरे पिता और हीरो मोटोकॉर्प के फाउंडर चेयरमैन डॉ. बृजमोहन लाल मुंजाल ने दुनिया भर में अरबों लोगों को प्रेरित किया। उनका विजन भारतीय वाहन उद्योग और भारतीय उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सफल रहा और वे अपने पीछे सरलता, इनोवेशन, साहस और ईमानदारी की विरासत छोड़ गए। उनके लिए, व्यापार लाभ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह लोगों और समुदाय दोनों के बारे में था।

100 चुने गए लोगों के लिए बड़ी ही सावधानी से तैयार की गई मोटरसाइकिल, केवल आमंत्रण पर उपलब्ध

उनकी 101वीं जयंती के पूरे होने के जश्न के बीच मुझे 'द सेंटेनियल' को लॉन्च करते हुए बेहद खुशी और गर्व हो रहा है - यह मोटरसाइकिल उनकी विरासत के सम्मान में तैयार किया गया एक चमत्कार है। 'द सेंटेनियल' केवल एक ऐतिहासिक मोटरसाइकिल नहीं है, बल्कि स्टील और कार्बन फाइबर से तैयार किया गया एक संस्मरण है। इस शानदार मशीन का डिजाइन, इंजीनियरिंग और तकनीक सभी हमें हमेशा प्रेरित करने वाले फाउंडर की अमिट छाप को दर्शाते हैं।

उनके समावेशी नजरिये ने हीरो समुदाय में हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों, डीलर्स, भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों समेत सभी को शामिल किया। इन 100 दिनों में, हम उस व्यक्ति को याद करते हुए जश्न मनाएंगे, जिन्होंने इस सबकी शुरुआत की। मैं सभी को डॉ. बृजमोहन लाल मुंजाल को उनकी 101वीं जयंती पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं।'- **डॉ. पवन मुंजाल**

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।